संपादकीय

जवाबी कार्रवाई से व्यापार युद्ध की आशंका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ हमले और चीन की जवाबी कार्रवाई से विश्व के तमाम शेयर बाजार लहूलुहान हुए हैं। कई अन्य देशों की भी जवाबी कार्रवाई के फैसले से दीर्घकालीन व्यापार युद्ध की आशंका बलवती हो गई है। जिससे पूरी दुनिया में मंदी आने की चेतावनी दी जा रही है। निश्चित तौर पर इससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस संशय और अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर बिकवाली से दुनिया के तमाम शेयर बाजार धराशायी हुए हैं। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में टैरिफ वॉर के और बढ़ने की आशंका है क्योंकि चीन ने नौ अप्रैल को होने वाली विश्व व्यापार संगठन की बैठक में 'नई व्यापार चिंता' के रूप में अमेरिका की टैरिफ नीति का मुखर विरोध करने का फैसला किया है। चीन का मानना है कि अमेरिका के एकतरफा संरक्षणवाद का दुनिया के देशों को विरोध करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की सुरक्षा के लिये एक व्यापक गठबंधन बनाने की जरूरत बतायी है। इन हालात में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ थोपने के फैसले को वापस लेंगे? या फिर पहले की तरह टैरिफ लगाने की धौंस देते रहेंगे। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि जिद्दी ट्रंप अपने बढ़े कदमों को पीछे खींचेंगे। यहां सवाल यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने वाले देश पलटवार करने में कितने सक्षम हैं। वहीं भारत ने दीर्घकालीन व व्यापक हितों को देखते हुए टकराव टालने का प्रयास किया है और बातचीत का रास्ता चुना है। लेकिन इस अनिश्चितता के दौर में निवेशकों में बढ़ती असुरक्षा ने भारत सरकार पर नीतिगत फैसले लेने के लिये दबाव बनाया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी संभावना है कि चीन व प्रतिकार करने वाले अन्य देशों के दबाव के कारण ट्रंप अपनी आ ामक रणनीति को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। विडंबना यह है कि अमेरिका राष्ट्रपति के इन कदमों से खुद अमेरिका के लिये भी बड़ी आर्थिक चुनौती पैदा हो सकती है। येल विश्वविद्यालय में बजट लैब के एक विश्लेषण के अनुसार ट्रंप सरकार के प्रतिशोधात्मक टैरिफ से औसत अमेरिकी परिवार को सालाना चार हजार दो सौ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं अमेरिका में मंदी और तेज मुद्रास्फीति का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं भारत जैसे अन्य विकासशील व विकसित देशों को आशा है कि वैश्विक व घरेलू दबाव ट्रंप को उनकी भूल का अहसास कराएगा। जिससे वे अधिक आर्थिक अराजकता पैदा करने वाले फैसलों से पीछे हटेंगे। वैसे एक हकीकत यह भी है कि अमेरिका अपने कई उत्पादों के लिये अन्य देशों पर निर्भर है। उसके उद्यमियों ने भी दूसरे देशों में औद्योगिक यूनिट लगा रखे हैं।

विनोद शर्मा, संपादक

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के रोडमैप के कायल हुए सदस्य देश, सुशासन व विकास को मिलेगी गति

कमलेश पांडे

इन नीतिगत निर्णयों से साफ है कि बिम्सटेक में भारत अपना वर्चस्व कायम रखते हुए एक बड़ी भूमिका निभाने को तैयार दिखाई दे रहा है। उसने इस क्षेत्रीय मंच को महत्व देने के साथ ही यहां पर अपना दबदबा बरकरार रखने की कोशिश की है। इस बाबत अंतरराष्ट्रीय मामलों के एशियाई जानकारों का कहना है कि भारत की मौजूदा नीतियों और नजरिए ने इस मंच को उम्मीद से बड़ा आकार प्रदान किया है। इससे सार्क के अप्रासंगिक होने की अटकलों के साथ ही भारत ने बिम्सटेक समूह सहित अन्य क्षेत्रीय मंचों को भी व्यापार और सहयोग के एक बड़े मंच के रूप में चिन्हित करते हुए अपनी भूमिका को मजबूत किया है ताकि चीनी चुनौतियों से वह आसानी पूर्वक निबट सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिम्सटेक में सभी सहयोगी देश अपने-अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व पर ही निर्भर हैं। वहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की पड़ोस पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और इंडो-पैसिफिक के लिए विजन पर स्पष्ट फोकस करने से इस समूह को आशातीत गति मिली है। चूंकि भारत ने ही बिम्सटेक सचिवालय को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों को आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि बिम्सटेक में सबकुछ करने की क्षमता है। इसलिए साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंक, मादक पदार्थों और मानव तस्करी पर रोक लगानी होगी। थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के रोडमैप पर सभी सदस्य देश कायल हुए। इससे सुशासन व विकास को गति मिलने के आसार बढ़ गए हैं। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकाक में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में गत 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को भाग लिया। जिसका विषय था- ÷बिम्सटेक= समृद्ध, लचीला और खुला।÷ इस दौरान सभी सदस्य देशों का ध्यान क्षेत्रीय सहयोग को और अधिक मज़बूत करने और आसन्न प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर था। तभी तो इस शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मोदी ने सदस्य देशों, यथा- थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान के सामने आपसी साझेदारी मजबूत करने के लिए 21 बिंदुओं का एक्शन प्लान पेश किया, जिसपर सबने सहमति जताई। वहीं, उन्होंने सभी सदस्य देशों को भारत की भुगतान प्रणाली %यूपीआई% से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। ताकि उनके पारस्परिक व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र को एक नए मुकाम पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने यहां तक कहा कि सदस्य देश यदि इससे जुड़ते हैं तो सबका भला होगा। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत करते हुए उनके देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उम्मीद जताई कि माहौल खराब करने वाले किसी भी बयान से बचना सबसे बेहतर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बंगलादेश के लिए भारत का समर्थन जारी रहेगा। क्योंकि भारत-बंगलादेश के रिश्ते बहुत पुराने हैं। भारत व्यवहारिकता के आधार पर बंगलादेश से सकारात्मक सम्बन्धों को नए आयाम पर पहुंचाने का पक्षधर है। उन्होंने सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों को आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि बिम्सटेक में सबकुछ करने की क्षमता है। इसलिए साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंक, मादक पदार्थों और मानव तस्करी पर रोक लगानी होगी। इस दिशा में सदस्य देशों के बीच गृह मंत्री स्तर के तंत्र को मिली मंजूरी भी स्वागत योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सभी सदस्य देशों को तकनीक के क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित करना है। उन्होंने भारत में बिम्सटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ़ॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। मोदी ने सदस्य देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिम्सटेक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के गठन का प्रस्ताव दिया। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में आए म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हेंग से मुलाकात में कहा कि भारत भूकम्प से बुरी तरह प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए तैयार है। जबकि मेजबान थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा ने बताया कि सभी सदस्य देश भूकंप के बाद राहत व बचाव कार्य को तेज करने के लिए राजी हुए हैं। जहां तक छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातों का सवाल है तो इस दौरान कई अहम प्रस्ताव रखे गए, जिनपर मिलजुलकर काम करने का निर्णय लिया गया। इस शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन घोषणा और बैंकॉक विज़न 2030 को अपनाया गया, जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिये एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई। जिसमें भारत द्वारा घोषित प्रमुख पहल इस प्रकार है। पहला, बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र के तहत भारत ने आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। इसने बिम्सटेक में शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर एक पायलट अध्ययन का भी प्रस्ताव रखा। वहीं, बिम्सटेक देशों के युवा राजनयिकों की हर साल भारत में प्रशिक्षण देने की बात भी रखी गई। जबकि, सदस्य देशों के छात्रों को भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और नालंदा विवि में छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया। दूसरा, बोधि कार्यक्रम के तहत भारत ने बिम्सटेक देशों के विभिन्न पेशेवरों के लिये कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिये बोधि कार्यक्रम (मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिये बिम्सटेक) की शुरुआत की। तीसरा, कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत ने बिम्सटेक क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा और कहा कि टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर सदस्य देशों में कैंसर उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी नई शोध केंद्र बनाएंगे। चतुर्थ, वाणिज्य मंडल एवं व्यवसाय शिखर सम्मेलन के तहत सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये बिम्सटेक वाणिज्य मंडल की स्थापना और वार्षिक बिम्सटेक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का प्रस्ताव किया गया। पंचम, लोगों से लोगों के बीच संबंध की रणनीति के तहत भारत ने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिये एक सकारात्मक पहल की घोषणा की, जिसमें बिम्सटेक एथलेटिक्स मीट (2025), प्रथम बिम्सटेक खेल (2027), समूह की 30वीं वर्षगाँठ, बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन और युवा जुड़ाव के लिये हैकाथॉन, सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने के लिये युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्चुअल ऑटिज़्म के शिकंजे में बच्चे

डॉ. मोनिका शर्मा

बहुत छोटे बच्चों का भी फोन या टीवी स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना उनमें इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल की लत पैदा कर रहा है। जिससे वर्चुअल ऑटिज़्म का जोखिम बढ़ जाता है। बेहतर है अभिभावक उन्हें गैजेट्स से दूर रखें। बच्चों को वर्चुअल नहीं बल्कि असली संसार से जोड़ना चाहिये। ताकि उनका प्राकृतिक सामाजिक-भावनात्मक तौर पर संतुलित विकास हो। स्मा र्ट गैजेट्स को दिया जा रहा समय बच्चों के समग्र विकास पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। बोलने-समझने की उम्र से पहले ही स्क्रीन में झांकते रहने की आदत तो संवाद और सामाजिकता के मोर्चे पर मासूमों के सहज विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कभी गेम, कभी कार्टून। पलक तक झपकाना भूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों का स्क्रीन के संसार में गुम रहना बहुत सी व्याधियों को न्योता देने वाला है। परवरिश के परम्परागत रंग-ढंग की जगह ले रहा तकनीकी जाल बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़्म का शिकार बना रहा है। बहुत छोटे बच्चों में स्क्रीन यानि टेलीविजन, स्मार्ट फोन, टैबलेट जैसे गैजेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल से वर्चुअल ऑटिज़्म की समस्या पैदा होती है। आभासी संसार में खोये रहने वाले बच्चे सामाजिक संपर्क बनाने में असहज महसूस करते हैं। देरी से बोलना सीखते हैं। दूसरी की बात समझने में कठिनाई होने लगती है। कई मामलों में दोहराव पूर्ण व्यवहार जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में अभिभावक मोबाइल आदि की स्क्रीन से बच्चों को दूर रखें। बता दें कि अप्रैल माह ऑटिज़्म की समस्या कोई लेकर अवेयरनेस लाने से जुड़ा है। हालिया वर्षों में परवरिश के मोर्चे पर टेक्निकल गैजेट्स के इस्तेमाल की अति से बच्चों को बचाने की ज़िम्मेदारी भी जुड़ गई है। यह डिजिटल व्यस्तता बालमन को कमोबेश हर मामले में नुकसान पहुंचाने वाली है। बच्चों के मानसिक-मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करने वाली वर्चुअल ऑटिज़्म समस्या कई दूसरी व्याधियों की भी जड़ है। चिंतनीय है कि जीवन के शुरुआती पड़ाव पर ही स्क्रीन को देखते रहने से वर्चुअल ऑटिज़्म के घेरे में आ रहे बच्चों का अटेन्शन स्पैन भी कम हो जाता है। बर्ताव में चिड़चिड़ापन और विचारों में उलझन-अस्पष्टता जगह बना लेती है। अपना नाम सुनकर भी रिएक्ट नहीं करते। बोलते समय हकलाते हैं। ऐसे बच्चे हाइपरएक्टिव हो जाते हैं। अकेलेपन और अनिद्रा की समस्या घेर लेती है। बहुत से बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून चरित्र या किसी ऑनलाइन खेल के कैरेक्टर की तरह बोलने-बतियाने लगते हैं। कम उम्र में बढ़ते स्क्रीन टाइम से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं। आम जीवन से कट जाने वाले ऐसे बच्चे फोकस्ड नहीं रह पाते। किसी भी बात या काम पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाना आगे चलकर व्यक्तिगत ही नहीं, अकादमिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि बच्चों के प्राकृतिक विकास को बाधित करने वाली इस समस्या को लेकर सजगता आवश्यक है। अभिभावक कभी अपनी सहूलियत के लिए तो कभी तकनीकी उपकरणों को मनोरंजन का माध्यम भर मानने के चलते बहुत छोटे बच्चों को भी स्क्रीन की दुनिया में व्यस्त कर देते हैं। धीरे-धीरे मासूमों को कुछ न कुछ देखते रहने की लत लग जाती है। ऐसे मामले भी विशेषज्ञों के पास पहुंचे हैं कि मात्र छह महीने के बच्चे भी स्क्रीन में देखे बिना खाना नहीं खाते। सालभर के बच्चे अपनों की आवाज़ को भी नहीं पहचानते। गैजेट्स के साथ बहुत अधिक समय बिताने वाले बच्चों को हरदम स्क्रीन पर दिखते कंटेन्ट से एकतरफा संवाद सुनने की आदत हो जाती है। जिसके चलते सहजता से कुछ बोल नहीं पाते। बातचीत के सहज हावभाव नहीं सीखते। पहले बहुत छोटे बच्चों का समय घर के बड़े बुजुर्गों या पेरेंट्स के साथ बीतता था। सहज इंसानी बातचीत सुनते हुए बड़े होने वाले बच्चे भी आसानी से बोलना सीख जाते थे। हर तरह के मनोभाव को जताना आ जाता था। बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम ने दूसरों की बातों को सुनना-समझना भुला दिया है। बालमन सहज प्रतिक्रिया भूल गया है। इतना ही नहीं बच्चे दूसरों से मेलजोल में भी असहज महसूस करते हैं। इन सभी समस्याओं का हल गैजेट्स से दूरी बरतना ही है। अभिभावक ही बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। संभव हो तो 5 साल की उम्र तक के बच्चों को डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह दूर ही रखें। वर्चुअल ऑटिज़्म पांच-सात वर्ष से छोटे बच्चों में ही अधिक होता है।

अगड़ी जातियों के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल- कांग्रेस को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ?

संतोष कुमार पाठक

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के जनाधार को लगातार बढ़ाने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ही राहुल गांधी अब तक तीन बार बिहार जा चुके हैं। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दल इस विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, जिसमें विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी नंबर वन की भूमिका में है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन है,जिसमें कांग्रेस दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस के नेता विपक्षी गठबंधन के लिए महागठबंधन शब्द की बजाय इंडिया गठबंधन का ही प्रयोग करने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के जनाधार को लगातार बढ़ाने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ही राहुल गांधी अब तक तीन बार बिहार जा चुके हैं। अपने मिशन बिहार के तहत राहुल गांधी सोमवार (7 अप्रैल) को बिहार की धरती पर थे। पिछले कुछ महीनों के दौरान उनकी यात्राओं की बात करें तो यह राहुल गांधी का तीसरा बिहार दौरा था। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी और 4 फरवरी को बिहार के दौरे पर गए थे। लेकिन अपने बिहार दौरे के दौरान, राहुल गांधी ने सोमवार को जिस अंदाज में अपर कास्ट यानी अगड़ी जातियों पर हमला बोला,वो सबके लिए काफी चौंकाने वाला रहा। राहुल गांधी ने कहा कि, ÷इस देश में अगर आप अपर कास्ट के नहीं हैं, तो आप सेकंड क्लास सिटिजन हैं। ये बात मैं यूंही नहीं कह रहा। यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सिस्टम को बहुत गहराई से देखा और समझा है। हमने तेलंगाना में जातिगत जनगणना की और उसके परिणामों को देखते हुए तेलंगाना में आरक्षण बढ़ा दिया। मैंने खुद नरेंद्र मोदी के सामने कहा है कि अगर आपकी सरकार आरक्षण की दीवार नहीं खत्म करेगी तो हम आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा वाली दीवार तोड़ देंगे। राहुल गांधी यहीं नहीं थमे। उन्होंने अगड़ी जातियों के खिलाफ बाकायदा एक माहौल बनाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुनें और ये बहुत जरूरी कदम है। पहले हमारे जिला अध्यक्षों में अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन अब नई लिस्ट में दो तिहाई लोग- ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। मैंने और खरगे जी ने बिहार की टीम को साफ संदेश दे दिया है कि आपका काम- बिहार की गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करना है। दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब सामान्य वर्ग और महिलाओं को जगह देना है। बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहां के नेताओं ने बिहार को जातियों के आधार पर खंड-खंड बांटने का काम किया है। रही-सही कसर नीतीश कुमार ने ओबीसी में से ईबीसी और दलितों में से महादलितों को निकाल कर पूरी कर दी है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने और कांग्रेस के जनाधार को मजबूत बनाने के लिए ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित और महिलाओं की बात करें, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय और सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भी पार्टी आलाकमान की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी से अगड़ी जातियों को लेकर इस तरह की भाषा की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती है। जबकि कांग्रेस और खासतौर से गांधी परिवार ने बीडीएम अर्थात बी से ब्राह्मण (इसमें तमाम अगड़ी जातियों को जोड़ा जाता है), डी से दलित और एम से मुस्लिम फॉर्मूले के आधार पर दशकों तक देश पर राज किया है। बिहार में भी इसी फॉर्मूले के आधार पर दशकों तक कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि दलित और ओबीसी मतदाताओं को एक साथ नहीं साधा जा सकता। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद यूपी के दलितों ने अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। बिहार में भी लालू यादव अपनी ही पार्टी के दिग्गज दलित नेता और बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास को जनता दल विधायक दल की बैठक में हरा कर ही 1990 में पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में राहुल गांधी जिस अंदाज में एक ही साथ पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असफल होना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी को शायद यह पता नहीं है या हो सकता है कि उन्हें अब तक उनके करीबी लोगों ने यह नहीं बताया है कि बीजेपी समेत बिहार में चुनाव लड़ रहे तमाम राजनीतिक दलों ने ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित को जातियों के हिसाब से बांट कर, उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां बहुत ही कम स्कोप बचता है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि अगड़ी जातियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर, राजनीति का सफर शुरू करने वाली मायावती भी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री तभी बन पाई थी, जब उन्होंने अगड़ी जातियों को भी बसपा के साथ जोड़ा था। बिहार में दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी ने पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। ऐसे में अगर वह गांधी परिवार के पुराने विनिंग फॉर्मूले पर अमल करते हुए अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश करते तो कांग्रेस का संगठन और ज्यादा मजबूत होता नजर आता। बिहार में वर्ष 2022 में कराए गए जाति सर्वे में आए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सवर्ण वर्ग की कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा यानी 15.52 प्रतिशत है।

तुलसी के पौधे से चींटियां निकलना शुभ या अशुभ, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

अनन्या मिश्रा

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि तुलसी के पौधे में किसी तरह की समस्या होने लगती है तो उसको नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल, तुलसी के पौधे से बेमौसम पत्तियों का झड़ना, पौधे का सूखना और कीट-कीड़े लगना भी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं तुलसी का पौधा भगवान श्रीहरि विष्णु को भी प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि तुलसी के पौधे में किसी तरह की समस्या होने लगती है तो उसको नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल, तुलसी के पौधे से बेमौसम पत्तियों का झड़ना, पौधे का सूखना और कीट-कीड़े लगना भी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से जोड़कर देखा जाता है। वहीं तुलसी का पौधा सूखना भी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का एक संकेत माना जाता है। वहीं इस पर चींटी या फिर कीड़ों का लगना भी शुभ या अशुभ तरीके से देखा जाता है। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी के पौधे से चींटियों के निकलने या लगना शुभ या अशुभ कैसा संकेत माना जाता है।

तुलसी के पौधे से चींटियां निकलने का मतलब

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। इसको मां लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इस पौधे से चीटियां निकलने का विशेष ज्योतिष में विशेष संकेत माना जाता है। हालांकि चींटियों के रंग और उनकी गतिविधियों पर यह निर्भर करता है कि यह शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत है। ज्योतिष और वास्तु में काली चीटियों का नाता राहु और शनि से माना जाता है। तो वहीं लाल चीटियों का मंगल ग्रह से नाता माना जाता है।

काली चींटियां: वहीं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे से काली चीटियां निकलना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे से काली चीटियां निकलना घर में आर्थिक संकट, शनि दोष और राहु की महादशा के संकेत हो सकते हैं। वहीं अगर काली चीटियों ने अंडे दे दिया तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। वहीं तुलसी के पौधे से काली चीटियों की रेल निकल रही है, तो यह घर-परिवार में धन हानि या आर्थिक संकट का भी संकेत हो सकता है। तुलसी के पौधे से काली चीटियों का निकलना परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा या मनमुटाव की संकेत को दिखाता है। घर-परिवार में किसी की हेल्थ बिगड़ने का भी संकेत हो सकती है।

लाल चींटियां: ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे से लाल चींटियों को निकलना या आसपास दिखाई देना शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे से लाल चीटियां निकल रही हैं, तो यह धन आगमन का संकेत हो सकता है। वहीं तुलसी के पौधे से लाल चीटियां निकलना किसी अच्छे समाचार या फिर सफलता का भी संकेत हो सकता है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि घर-परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है और यह सुख-शांति का भी संकेत हो सकता है। तुलसी के आस-पास लाल चींटियां दिखाई देने लगे तो लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। कार्यों में सफलता मिलती है और यह सुख-समृद्धि का भी संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर तुलसी के गमले में लाल चीटियों ने अंडे दे दिए हैं या पौधे को नुकसान पहुंचाना शुरूकर दिया।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा एन.व्ही.आर. पब्लिकेशन हाउस S-99/33 नीलबड़ रोड भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, एफ- 12 द्वितीय तल गोयल निकेत एमपी नगर जोन-1 भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित
पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708 *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। RNI No.- MPHIN/2016/68059 E-mail - peoplespravakta@gmail.com